IJGMRA | ISSN (Online): 3107-6483
October-December 2025 | Vol. 01 | Issue 3
Website: www.thearyapublication.com

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के लिए अध्यापक शिक्षा

डॉ. प्रिया जौहरी[1] & *डॉ. अमित रत्न द्विवेदी[2]

[1]पूर्व कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता, अध्यापक शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
Orchid: https://orcid.org/0009-0005-1598-8028
*[2]जिला समन्वयक, ह्यूमाना पीपुल टू पीपुल इंडिया, डायट, गया, बिहार
Orchid: https://orcid.org/0009-0001-0796-9653

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18207500
Accepted on: 31/12/2025 Published on: 10/01/2026

सारांश:

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का उद्देश्य छात्रों को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण देना है, जिससे वे रोजगार योग्य बन सकें। इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल-आधारित शिक्षा में दक्ष हों ताकि वे छात्रों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित कर सकें। पारंपरिक शिक्षण से अलग, व्यावसायिक शिक्षा में व्यावहारिक प्रशिक्षण, केस स्टडी, कार्यशालाएं और उद्योग-अनुभव आधारित शिक्षण की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर आधारित अध्यापक शिक्षा शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों, डिजिटल उपकरणों और आधुनिक पाठ्यक्रमों से परिचित कराती है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में शिक्षा और उद्योग के बीच तालमेल आवश्यक है। प्रशिक्षित अध्यापक उद्योग की आवश्यकताओं को समझकर विद्यार्थियों को उसी अनुसार तैयार कर सकते हैं, जिससे वे सीधे कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से काम कर सकें। व्यावसायिक क्षेत्र में नई तकनीकों और कौशलों का तेजी से विकास हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यापक शिक्षा न केवल शिक्षकों को आवश्यक कौशल प्रदान करती है, बल्कि उन्हें नवाचारशील, उद्योग-उन्मुख और छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत बनने में भी सक्षम बनाती है। इससे न केवल छात्रों का विकास होता है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति भी सुनिश्चित होती है।

प्रस्तावना: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक न केवल बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, बल्कि हमारे राष्ट्र की दिशा को भी निर्धारित करते हैं। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण भारत में शिक्षक समाज के सबसे अधिक सम्मानित सदस्य माने जाते थे, और केवल योग्य, विद्वान एवं समर्पित व्यक्ति ही इस पद को ग्रहण

करते थे। पारंपरिक रूप से, समाज शिक्षकों या गुरुओं को ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों के प्रसार के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराता था। हालांकि, वर्तमान समय में शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता, नियुक्ति प्रक्रिया, पदस्थापन, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति अपेक्षित स्तर पर नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि शिक्षकों की गुणवत्ता और उनका उत्साह वांछित मानकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए, अध्यापक शिक्षा के नए प्रतिमानों को गढ़ने की आवश्यकता है । इससे न केवल शिक्षा क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों को आकर्षित किया जा सकेगा, बल्कि उन्हें इस पेशे में आने के लिए प्रेरित भी किया जा सकेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। शिक्षकों की अध्यापक शिक्षा में निरंतर अनुसंधान और नवाचार नए शिक्षण तरीकों का विकसित करता है | आज हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो छात्रों की व्यावसायिक उन्नति करने और उनको कौशलों से परिपूर्ण कर सकें | हमें ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो केवल ज्ञान देने न दे बल्कि वे छात्रों को करियर निर्माण, व्यावसायिक कौशल विकास और आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार करने वाले मार्गदर्शक हो | आज के प्रतिस्पर्धी दौर में शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि अब उनकी भूमिका केवल विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना नहीं है बल्कि उन्हें प्रायोगिक एवं उद्योग-आधारित कौशल भी प्रदान करना है | इस भूमिका का निर्वाहन करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के लिए अध्यापक शिक्षा की एक आवश्यक आयाम हैं |

व्यावसायिक शिक्षा:

भारत में व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार रूपांतरित किया जा रहा है। वर्तमान समय में सरकार और विभिन्न शैक्षिक संस्थान इसे मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से छात्रों को रोजगार योग्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं।

1. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और व्यावसायिक शिक्षा**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को एक मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को केवल डिग्री नहीं, बल्कि रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाना है। इस नीति के तहत छात्र न केवल अकादमिक रूप से सक्षम होंगे, बल्कि वे आधुनिक और तकनीकी कौशल से भी लैस होंगे, जिससे भारत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा

नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और युवाओं को अधिक रोजगारोन्मुखी और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है। इस नीति में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है ताकि छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहें, बल्कि वे उद्योगों और कार्यस्थलों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 6 से 12 के बीच इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा ताकि वे व्यावसायिक कौशल सीखने और छात्रों को हैंड्स-ऑन लर्निंग, प्रायोगिक अनुभव और उद्योग से जुड़े कौशल सिखाने की अनुसंशा करती हैं। छात्रों को पारंपरिक विषयों (गणित, विज्ञान, भाषा) के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल (जैसे बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग, एआई, कृषि आदि) का विकल्प दिया जाएँ। मल्टी-डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया जाएगा ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकें। शिक्षा ऐसी हो जो इंडस्ट्री और अकादमिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे SWAYAM, DIKSHA, और अन्य ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं को शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा। स्थानीय कौशल के साथ-साथ इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक कौशल पर भी जोर दिया गया है। इससे युवा न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी रोजगार के लिए तैयार होंगे। उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच संबंध मजबूत किए जाएंगे ताकि छात्र सीधे रोजगार योग्य बन सकें। विश्वविद्यालयों में इनोवेशन लैब्स, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर्स और स्किल हब बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों को विभिन्न प्रकार के कौशल, विशेष रूप से सॉफ्ट स्किल, के लिए अल्पकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। भारत की युवा पीढ़ी को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना आवश्यक है ताकि देश के जनसांख्यिकीय लाभ को पूरी तरह से उपयोग में लाया जा सके। इसके लिए शिक्षा और उद्योग के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने व्यावसायिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने पर बल दिया है। इसके मुख्य बिंदु हैं:

कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा: विद्यार्थियों को कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा और कौशल आधारित प्रशिक्षण से परिचित कराया जाएगा। 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य: 2025 तक स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक 50% विद्यार्थियों को किसी न किसी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की

योजना बनाई गई है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम: स्कूली और उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय रोजगार अवसरों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करने की सिफारिश की गई है।

अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण:

विद्यार्थियों को एक लचीला मार्ग प्रदान किया जाएगा, जिससे वे व्यावसायिक और पारंपरिक शिक्षा के बीच स्विच कर सकें।

2. राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) का कार्यान्वयनराष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (National Skills Qualifications Framework - NSQF) को 2013 में लागू किया गया था, जिसे अब और प्रभावी बनाया जा रहा है। इसके तहत: व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। इसे स्तर-आधारित शिक्षा प्रणाली (Level 1 से Level 10) में विकसित किया गया है, जिससे विद्यार्थी धीरे-धीरे उच्च स्तर के कौशल प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को क्रेडिट आधारित प्रणाली से जोड़कर उच्च शिक्षा के साथ समन्वित किया जा रहा है।

3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया मिशन: युवाओं की रोजगार-तैयारी की दिशा में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ युवाओं की आबादी जनसांख्यिकीय लाभ (demographic dividend) के रूप में देखी जाती है, वहाँ कौशल विकास और रोजगार-उन्मुख शिक्षा की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इसी संदर्भ में वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं को अल्पकालिक एवं उद्योग-उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना रहा है (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship [MSDE], 2015)। यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अंतर्गत संचालित की जाती है, जहाँ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाते हैं (NSDC, 2020)। विभिन्न सरकारी रिपोर्टों और मूल्यांकन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि इस योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। हालांकि, शोध यह भी संकेत देते हैं कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उद्योग से वास्तविक जुड़ाव तथा प्लेसमेंट की प्रभावशीलता राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार समान नहीं रही है (Mehrotra & Parida,

2019)। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना की पहुँच व्यापक होने के बावजूद इसके परिणामों की सतत निगरानी और सुधार आवश्यक है।

स्किल इंडिया मिशन के व्यापक ढाँचे के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही, भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय जैसी नई संस्थाओं की स्थापना ने रोजगार-केंद्रित उच्च शिक्षा को नया आयाम प्रदान किया है (MSDE, 2019)। उच्च शिक्षा में वोकेशनल कोर्सों के समावेशन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी दिशानिर्देश यह दर्शाते हैं कि पारंपरिक शिक्षा और कौशल-आधारित शिक्षा के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है (UGC, 2020)।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) के अंतर्गत स्नातक और डिप्लोमा छात्रों को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा और कार्य-अनुभव के बीच सेतु स्थापित हो सके (MSDE, 2018)। ड्यूल डिग्री जैसी व्यवस्थाएँ यह संभावना उत्पन्न करती हैं कि विद्यार्थी एक साथ अकादमिक योग्यता और व्यावसायिक दक्षता दोनों अर्जित कर सकें। हालांकि, कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान इस मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाए हैं (Tilak, 2021)।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कौशल प्रशिक्षण का बदलता स्वरूप

डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ कौशल प्रशिक्षण का स्वरूप भी तीव्र गति से परिवर्तित हुआ है। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण अब समय और स्थान की सीमाओं से परे उपलब्ध हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन कोर्सों की बढ़ती संख्या इस परिवर्तन का प्रमाण है (World Economic Forum, 2020)।

हालाँकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि डिजिटल प्रशिक्षण की प्रभावशीलता डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सीखने के वातावरण पर निर्भर करती है। ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच की सीमाएँ अब भी बनी हुई हैं, जिससे डिजिटल डिवाइड की समस्या सामने आती है (UNESCO, 2021)।

उद्योग शिक्षा साझेदारी: सिद्धांत से व्यवहार की ओर

वर्तमान कौशल विकास मॉडल में उद्योगों के साथ साझेदारी को एक केंद्रीय तत्व के रूप में देखा जा रहा है। सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत विभिन्न बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और औद्योगिक अनुभव को बढ़ावा दिया गया है (MSDE, 2020)। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर वास्तविक कार्यस्थल की समझ प्रदान करना है।

लेखक के क्षेत्रीय अनुभव और विभिन्न संस्थागत अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि कई बार इंटर्नशिप औपचारिकता तक सीमित रह जाती है, जिससे अपेक्षित कौशल विकास नहीं हो पाता (Mehrotra, 2018)। अतः उद्योग सहभागिता को नीति-स्तर के साथ-साथ क्रियान्वयन स्तर पर भी सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

आधुनिक शिक्षा में बहुआयामी कौशल और रोजगार-योग्यता का महत्व

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था और तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के संदर्भ में शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक उपलब्धि तक सीमित नहीं रह सकता। रोजगार-योग्यता (Employability) का आशय अब केवल नौकरी प्राप्त करने से नहीं, बल्कि निरंतर सीखने, कौशल अद्यतन और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता से है (Yorke, 2006)। इसी दृष्टि से नई शिक्षा नीति 2020 ने व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने और कार्यस्थल-तैयारी (workplace readiness) पर बल दिया है (Government of India, 2020)।

संज्ञानात्मक कौशल जैसे आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और निर्णय-निर्माण की क्षमता आज के कार्यस्थलों में अत्यंत आवश्यक मानी जा रही हैं। इसके साथ-साथ प्रभावी संप्रेषण, डिजिटल साक्षरता, नेतृत्व क्षमता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी रोजगार-योग्यता को सुदृढ़ करती हैं (OECD, 2019)। उद्यमिता-संबंधी कौशल युवाओं को केवल रोजगार-प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि रोजगार-सृजनकर्ता बनने के लिए प्रेरित करते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौशल विकास योजनाएँ युवाओं की रोजगार-तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, परंतु इनके प्रभाव को स्थायी और व्यापक बनाने के लिए उद्योग–शिक्षा सहयोग को और मजबूत करना आवश्यक है। कौशल-आधारित मूल्यांकन प्रणालियों का विकास, आजीवन सीखने (lifelong learning) को प्रोत्साहन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय कौशल केंद्रों की स्थापना इस दिशा में सहायक सिद्ध हो सकती है (OECD, 2020)। यदि इन पहलों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं और वास्तविक रोजगार अवसरों से जोड़ा जाए, तो ये योजनाएँ युवाओं को प्रतिस्पर्धी श्रम बाजार में सक्षम बनाने में प्रभावी योगदान दे सकती हैं।

"एक सक्षम व्यक्ति केवल रोज़गार प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह रोज़गार के नए अवसर भी उत्पन्न करता है।" भारत में 2030 तक दुनिया में सबसे बड़ी कार्यशील उम्र की जनसंख्या होगी, लेकिन मुख्यधारा की शिक्षा प्राप्त छात्रों के लिए लाभकारी रोजगार प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव लाने और एक नए दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने चरणबद्ध तरीके से सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया है। इस नीति के तहत, चार वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रमों सहित सभी डिग्री पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन तेजी से बदलती दुनिया में सफल, नवाचारशील, अनुकूलनशील और उत्पादक बनने के लिए कुछ आवश्यक विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी अनिवार्य है। भाषाओं में दक्षता के अलावा, जिन कौशलों और योग्यताओं का विकास आवश्यक है, वे हैं:-

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसंगत सोच
- रचनात्मकता और नवाचार
- सौंदर्यशास्त्र और कला की समझ
- मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति और संचार कौशल
- स्वास्थ्य और पोषण संबंधी ज्ञान
- शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल
- सहयोग और टीम वर्क
- समस्या समाधान और तार्किक सोच
- व्यावसायिक जागरूकता और कौशल
- डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग
- नैतिकता और नैतिक मूल्यों की समझ
- मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान एवं अनुप्रयोग
- लिंग संवेदनशीलता

- आर्थिक जागरूकता और नागरिकता कौशल
- भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ
- पर्यावरणीय जागरूकता, जल एवं संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और स्वच्छ भारत अभियान
- समसामयिक घटनाओं और स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों की समझ

इन कौशलों और क्षमताओं के विकास से विद्यार्थी न केवल अपने करियर में सफल हो पाएंगे, बल्कि समाज में एक जागरूक, उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक की भूमिका भी निभा सकेंगे।

शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एन.पी.एस.टी):

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारत की शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधारों के केंद्र में शिक्षक को रखती है। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक नागरिक के जीवन को प्रभावित करती है, और इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय पेशेवर मानक शिक्षक (NPST) का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उन लक्ष्यों को पूरा करना है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा समान रूप से उपलब्ध हो। शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यह आश्वासन देता है कि सभी शिक्षक उत्साही, प्रेरित, उच्च योग्य, अच्छी तरह प्रशिक्षित और सभी स्तरों पर शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए सुसज्जित हों। इसलिए, शिक्षा जगत में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना समय की मांग है। यह करियर के विभिन्न चरणों में शिक्षकों की आवश्यक योग्यताओं की पहचान करने में सहायता करता है। इसके अलावा, यह शिक्षकों की तैयारी, अभ्यास और प्रदर्शन में सुधार पर भी केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का प्रस्ताव है कि व्यावसायिक मानकों के आधार पर शिक्षण व्यवसाय को संचालित किया जाए जो उत्तरदायित्व, निर्वहन, निगरानी, शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति को सुनिश्चित करें | शिक्षकों के व्यावसायिक मानकों का एक संग्रह सक्षम हो सकता है

- एक शिक्षक के कार्य की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए,
- कार्य और सेवा की स्थितियों को बनाने के लिए,
- शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की पुनर्रचना करने के लिए,
- शिक्षकों के पंजीकरण के लिए,
- जीवन पर्यंत अधिगम तथा व्यावसायिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए,
- शिक्षा की योग्यता में एकरूपता स्थापित करने और गतिशीलता को सक्षम बनाने के लिए ,

- शिक्षा गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए,

शिक्षकों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षकों के उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को सुरक्षित करने के लिए यद्यपि मानकों के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया जाना आवश्यक हैं | उनका उपयोग करने के आधार भिन्न हो सकते है फिर भी मानकों का एक समान संग्रह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षक को और एक व्यवसाय के रूप में शिक्षक से संबंधित विभिन्न मामलों में नीति का सामान्य हो सकें | वर्तमान समय में भारत में ज्ञान के संदर्भ में व्यापक परिवर्तन हो रहा है | इसकी 21वीं सदीं की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना आवश्यक है | राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) 21वीं सदीं की शिक्षा की पहली शिक्षा नीति है जिसका उद्देश्य हमारे देश के विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है | शिक्षक वास्तव में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ते हैं इसलिए हमारे राष्ट्र के भविष्य के निर्माण करता है | सभी के लिए समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक व्यवसाय के विकास पर विशेष बल दिया और शिक्षकों के सभी सुधार को केंद्र में रखा गया है | एन.पी.एस.टी का उद्देश्य शिक्षक व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रेरित करना शिक्षकों को सशक्त बनाना और उन्हें अपना कार्य तथा संभव प्रभावी ढंग से करने में सहायता देना है | राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक (एन.पी.एस.टी) एक समान निर्देशिका वर्ष 2020 तक विकसित की गई | इस निर्देशिका का निर्माण एनसीटी, एनसीईआरटी विभिन्न स्तरों के क्षेत्र में शिक्षक सुधार और शिक्षक की तैयारी एवं उनके विकास में संगठन विशेष संगठन व्यावसायिक शिक्षा में विशेष निकाय तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के परामर्श से किया गया | इसमें विशेषज्ञ के पद के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की भूमिका के प्रति अपेक्षाओं तथा आवश्यक दक्षताओं को सम्मिलित किया गया है साथ ही समय-समय पर होने वाले निष्पादन मूल्यांकन मानकों का भी संचयन प्रत्येक चरण के लिए किया गया है। एन.पी.एस.टी निर्देशिका एक मार्गदर्शक निर्देश है और यह उन सभी हित धारकों की सहायता करती है जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों को तैयार करने की प्रक्रिया में सम्मिलित है| यह शिक्षिका को या शिक्षकों को उनके शिक्षक बनने के निर्णय से लेकर उनकी शिक्षक यात्रा पूरा करने तक कौशल विशाल विकास का एक स्पष्ट पत्र प्रदान करती है या निर्देशिका शिक्षक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षक तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है | एक सफल शिक्षक कार्य जीवन की तैयारी की यात्रा किसी व्यक्ति की शिक्षक शिक्षा प्रोग्राम में प्रवेश के पहले दिन से शुरू होती है | एन.पी.एस.टी उन दक्षताओं

का एक रेखा चित्र तैयार करता है जो एक शिक्षक प्रशिक्षु को शिक्षक व्यवसाय की तैयारी के प्रारंभिक चरणों में करनी चाहिए तथा जब कोई भावी शिक्षक शिक्षक व्यवसाय में प्रवेश लेने का निर्णय लेता है तो एन.पी.एस.टी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित किया जाएगा |

अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप की भूमिका

कौशल विकास के क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये उच्च शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ने का कार्य करती हैं। इसे उद्योग के अनुकूल कुशल कार्यबल तैयार करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। इससे छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिलती हैं।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों को अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप को स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत, तकनीकी संस्थानों के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें 50,000 से अधिक छात्रों ने पहले ही पंजीकरण कर लिया है। यह दिशानिर्देश उच्च शिक्षा संस्थानों को यह विकल्प प्रदान करते हैं कि वे स्नातक पाठ्यक्रम में कम से कम एक सेमेस्टर के लिए अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप को अनिवार्य करें। इसके अलावा, संस्थानों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे किसी भी वाणिज्यिक, गैर-वाणिज्यिक संगठन, उद्योग, उद्यम, सरकारी संस्थान या क्षेत्रीय कौशल परिषदों के सहयोग से इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने भी छात्रों की व्यावसायिक दक्षता और रोजगार संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक इंटर्नशिप पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से, सरकारी संस्थानों (जैसे आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय रेलवे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, MSME, स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट कंपनियां, गैर-सरकारी संगठन और अनुसंधान संस्थान) में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार अवसर:

भारत में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सके और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो।

1. **राष्ट्रीय स्तर पर पहल:**

कौशल भारत मिशन (Skill India Mission): इस कार्यक्रम के तहत, युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे रोजगार योग्य बन सकें। (PM India, 2025)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): इस योजना के माध्यम से, शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग और Recognition of Prior Learning (RPL) के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

जन शिक्षण संस्थान (JSS): यह पहल विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लक्षित करते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है।

राज्य स्तर पर प्रयास:

उत्तर प्रदेश: 2025-26 के बजट में, राज्य सरकार ने कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत, अब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योगों और एमएसएमई में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिले हैं। (अद्भुत समाचार, 2025)

राजस्थान: राज्य में 4,155 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है, जिससे छात्रों को अपने करियर की दिशा चुनने में सहायता मिल रही है।(राजस्थान शिक्षा विभाग, 2025)

रोजगार के अवसरों में वृद्धि:

भारत कौशल रिपोर्ट 2025: इस रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक भारतीय ग्रेजुएट्स की रोजगार क्षमता 7% बढ़कर 54.81% तक पहुँचने की उम्मीद है। प्रबंधन, इंजीनियरिंग, एमसीए, और विज्ञान स्नातकों की रोजगार क्षमता में भी वृद्धि देखी गई है। (अपनी पाठशाला, 2025)

आर्थिक सर्वेक्षण 2025: इस सर्वेक्षण में बताया गया है कि EPFO से जुड़े लोगों की संख्या 2019 में 71 लाख से बढ़कर 2024 में 131 लाख हो गई है, जो संगठित क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का संकेत है।(बिजनेस स्टैन्डर्ड, 2025)

कौशल विकास और रोजगार क्षमता के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया हैं:

संस्थान और उद्योग के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने के प्रभावी तरीके,

व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लिए विभिन्न मॉडल्स की खोज,

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (NSQF) की समीक्षा करके इसे व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण (ISCO) के अनुरूप बनाना, जिससे छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें।

इस तरह, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाकर, भारत अपने विशाल युवा कार्यबल को आत्मनिर्भर और रोजगार के योग्य बना सकता है।

संदर्भ:

- अद्भुत समाचार (2025). *प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना से उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि*. https://adbhutsamachar.com/news/14459
- अपनी पाठशाला (2025). *भारत कौशल रिपोर्ट 2025: भारतीय स्नातकों की रोजगार क्षमता में वृद्धि*. https://apnipathshala.com/daily-current-affairs/daily-current-affairs-hindi/india-skills-report-2025
- बीजनेस स्टैन्डर्ड (2025). *आर्थिक सर्वेक्षण 2025: युवा रोजगार और कौशल विकास के पहलू*. https://hindi.business-standard.com/economy/economic-survey-2025-employment-of-youth-to-skill-development-every-aspect-id-408927
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. https://www.education.gov.in/nep2020
- *केंद्र सरकार द्वारा कौशल विकास और रोजगार योजनाएँ* (2025). https://www.pmindia.gov.in/hi/news_updates/
- Kothari Commission. (1966). National Council of Educational Research and Training.
- McKinsey & Company. (2021). *Defining the skills citizens will need in the future world of work*. https://www.mckinsey.com
- Mehrotra, S. (2018). *India's skills challenge: Reforming vocational education and training to harness the demographic dividend*. Oxford University Press.
- Mehrotra, S., & Parida, J. K. (2019). India's skills development programme: Assessing its institutional framework and outcomes. *Economic and Political Weekly, 54*(21), 47–55.
- *स्वयं* (2023) *निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा मंच*. https://swayam.gov.in
- *राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS)* (2023).

- https://www.apprenticeshipindia.gov.in
- *राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति* (2015). https://www.msde.gov.in
- *प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)* (2023) . https://www.pmkvyofficial.org
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (2023). *दीक्षा (DIKSHA): ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल अवसंरचना*. https://diksha.gov.in
- *राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF)*. (2013) https://www.nsdcindia.org
- *भारत में कौशल अंतर विश्लेषण एवं प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र* (2020)
- https://www.nsdcindia.org
- नीति आयोग (2022) *भारत की कौशल विकास पहल: वर्तमान स्थिति एवं भावी परिदृश्य* https://www.niti.gov.in
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *OECD skills outlook 2019: Thriving in a digital world*. https://doi.org/10.1787/df80bc12-en
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *OECD skills outlook 2020: Navigating the COVID-19 crisis*. https://doi.org/10.1787/3c9be1ef-en
- *व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास में सरकारी पहल* (2023). https://www.pib.gov.in
- *राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा की पहल* (2025)
- https://www.instagram.com/rajeduofficial/reel/DEzoH7tBeDp/
- Tilak, J. B. G. (2021). *Education, skill development and employment in India*. Springer.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. https://unesdoc.unesco.org
- World Bank. (2021). *Skills development for employability in India*. https://www.worldbank.org
- World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020*. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020